श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में तीन और महत्वपूर्ण भाषायें—मैथिली, राजस्थानी और भोजपुरी—जोड़ने के विषय में यह विधेयक है।...

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I rise on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : With regard to this Bill by Shri Bhogendra Jha I have received a letter from Shri S. M. Banerjee that under rule 109 he wants to move a motion that the debate on this Bill be adjourned. Firsly, I would like to know the reasons. There can be only two or three reasons--Goverment want to introduce a similar Bill, Government want time to consider the matter or some other reason.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, if you will see the statement of Objects and Reasons. It seeks to include Maithali, Rajasthani and Bhojpuri in the Eighth Schedule to the Consittution. Maithili is a language which is spoken in a particular area of the country. Rajasthani is spoken in a large part of Rajasthan and the hon. Member, Dr. Karni Singh moved a similar Bill about that, saying that Rajasthani should be included in the Eighth Schedule. Bhojpuri is spoken over the half of UP and Bihar. The main idea of moving this adjournment is that government should make up its mind and give us a reply. Let them consider the whole matter and till then let it be adjourned. Even according to the government there is necessity for this. So, let them take up their mind and let them not delay it. That is why I am making this request to Shri Bhogendra Jha and to the Minister, through you, Sir, that the discussion on this Bill be adjourned.

MR DEPUTY-SPEAKER : I have not yet given my consent. I have only heard you. Now let me hear the Minister.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : May I invite the attention of the hon. Members opposite to what my colleague, Shri Gokhale, said on this question ? He said :

"I would request hon. Members to consider whether a more practical approach is not called for, whether a comprehensive examination, a second look, should not be given to the whole scheme of the Eighth Schedule I would appeal to the Mover to withdraw the Bill."

Then he says further :

"Government will certainly give very respectful attention to the trend of opinion in this House, as it must. Government will also have to consider side by side whether other languages ought to be considered and at the appropriate time Government will give due weight to the opinion expressed on these three languages as well as others."

This is what he said on the 23rd July, 1971. Therefore, so far as this question concerned, we will give all due thought and consideration to this matter.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In view of this, I give my consent for the moving of the motion.

SHRI S. M. BANERJEE : Under rule 109, I beg to move :

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill, by Shri Bhogendra Jha, be adjourned."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill, by Snri Bhogendra Jha, be adjourned."

The motion was adopted.

15.45 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Substitution of Article 43*)
by
Shri Bharat Singh Chauhan

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we will take up the Constitution (Amendment) Bill, 1971 by Shri Bharat Singh Chauhan.

श्री भारत सिंह चौहान (धार) : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के

संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

इस देश के सामने बेरोजगारी की समस्या एक गम्भीर समस्या है। हम देखते हैं कि पिछले 20-22 सालों में शासन बेरोजगारी को दूर करने में बिल्कुल असमर्थ रहा है। लेबर कमीशंस की जो रिपोर्टें देखने में आईं और तमाम दलों की ओर से जो सुझाव आये उनका मैंने अध्ययन किया और मैंने देखा कि सभी इस बात में एकमत हैं कि 20-22 सालों में यह शासन इस देश के नागरिकों को एम्प्लायमेंट नहीं दे पाया है। इस देश में लगभग 50 लाख पढ़े लिखे लोग तो बेकार हैं ही, उनके साथ-साथ बे-पढ़े लिखे लोगों के बारे में भी यह अधिकृत रिपोर्ट है कि एक करोड़ से भी ज्यादा वे लोग बेकार हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इसी तरह से भारत में बेकारी रही तो हम आर्थिक या सामाजिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। जब 20-22 सालों में भी यह शासन बेकारी को दूर नहीं कर सका तब मैंने इस विधेयक के अन्तर्गत यह सुझाव रखा है कि राष्ट्रपति स्वयं इस जिम्मेदारी को लें और इस सरकार को 1976 तक का मौका दिया जाये, यदि तब भी इस समस्या को यह हल नहीं करती है तो यहां पर एक सर्वदलीय सरकार कायम की जाये। मेरा यह अनुभव है—क्या लोक सभा और क्या राज्य सभा, जितनी भी यहां पार्टीज है, मैंने अध्ययन किया है कि ये सभी इस बात में एकमत हैं कि यह सरकार रोजी रोटी देने में अपने नागरिकों को बिल्कुल असमर्थ रही है। मैंने पिछली तमाम बहसों को अध्ययन किया है और यह पाया है कि कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसने इस बात के—पक्ष में अपने विचार प्रकट न किये हों और यह न कहा हो कि यह सरकार इस बेकारी की समस्या को हल करने में असमर्थ रही है...

15.48 hrs.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : Sir, there is no quorum

MR. CHAIRMAN : Let the bell be rung.

Now there is quorum.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मेरा पौइन्ट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य जो बिल लाये हैं उसमें रूल 69 के अनुसार जोकि इस प्रकार है :

> "A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite."

इसके अन्दर खर्चे का सवाल है। माननीय सदस्य करोड़ों रुपया खर्च कराना चाहते हैं। जैसे माननीय डा० कर्णी सिंह ने अपने बिल के साथ फाइनेंशियल मेमोरेन्डम लगाया है, उसी तरह माननीय चौहान को भी लगाना चाहिये था। उस मेमोरेन्डम की ऐबसेंस में यह बिल नहीं आ सकता।

श्री भारत सिंह चौहान : शासन जिस ढंग से इस समय काम कर रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर अपनी अक्लमन्दी से काम करे तो करोड़ों लोगों को धंधा मिल सकता है। यही मेरे प्रस्ताव का मकसद है।

अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली के बारे में एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह उस कब्र के समान है जिसके अंदर कीड़े हो गये हैं लेकिन ऊपर से सफेदी लगी हुई है। तो यह सरकार अपनी कार्य प्रणाली के कारण लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, मेरे प्वाइंट आफ आर्डर का जवाब दीजिये।

MR. CHAIRMAN : Shri Daga has raised a point of order. This Bill is an enabling Bill. It does not involve any financial obligations. It is only an enabling Bill. So, there is no point of

श्री भारत सिंह चौहान : इस बेकारी समस्या को लाइटली नहीं लेना चाहिये, बल्कि युद्ध स्तर पर लेना चाहिये। मैंने दोनों सदनों की कार्यवाही का अच्छी तरह से अध्ययन किया है, तमाम दलों ने इस बात को अनुभव किया है कि अगर बेकारी की समस्या हल नहीं होती है तो हमारा विकास रुक जायेगा। आर्थिक विकास भी समाप्त हो जायेगा।

आज सैंकड़ों कालेज खुल गये और हजारों की तादाद में वहां से पढ़ कर निकले हुए इंजीनियर बेकार घूम रहे हैं। शासन जिस ढंग से चल रहा है इससे दिन पर दिन बेकारी बढ़ती जा रही है। उसको रोका जाय।

ट्रांसपोर्ट और शिपिंग का ही उदाहरण है। तीन हजार मील का हमारा तट है, वहां पर अगर छोटे-छोटे पोर्टस का विकास किया जाय तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। इस बिल का उद्देश्य यही है कि अगर शासन 1976 तक इसमें फेल होता है, जिसका सम्बन्ध देश के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास से है, तो राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी हो जाती है।

विदेशों में शासन कुशलता से चलते हैं जिसकी वजह से इतनी भयानक बेकारी की स्थिति नहीं होती। लेकिन हमारे यहां तो सरकार की कम अक्ली की वजह से यह बेकारी की समस्या हमारे आर्थिक विकास को समाप्त कर रही है। आज कृषि प्रधान देश में करोड़ों की तादाद में खेतिहर मजदूर बेकार हैं। प्रधान मंत्री ने समय-समय पर कहा है कि इस समस्या का हल तीव्र गति से निकाला जाय। लेकिन काम उस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। तो कहने से ही काम नहीं हो जाता है। उसके लिए सही रूप से प्रयास भी करना होता है। यों दिखाया तो जरूर जाता है कि हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो योजनायें अमल में नहीं आ रही हैं। इसलिए जो मेरा सुझाव है उसको स्वीकार किया जाय कि अगर 1976 तक यह शासन इस समस्या को हल करने में सफल नहीं होता है तो सर्वदलीय सरकार बनाई जाय। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक बेकारी की समस्या हल नहीं होती है तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज को हल करने की सख्त आवश्यकता है। शासन को मेरी यह चेतावनी है कि अगर वह इसको हल नहीं करता है तो वह किसी में सफल नहीं हो सकता है।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken, into consideration."

SHRI M. C. DAGA : I beg to move :

"That the Bill be circulated for purpose of eliciting opinion thereon by the 1st September, 1971." (1)

16.00 hrs.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): सभापति महोदय, इस मुल्क में बेकारी जरूर है, लेकिन इस बेकारी के लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपोजीशन है क्योंकि वह गवर्नमेंट को कोई काम नहीं करने देता। आप देखिए कि अभी जन संघ के श्री चौहान बात कर रहे थे। बंगला देश के मामले में गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो मुल्क के कोने-कोने में हजारों लोगों को ला कर जनसंघ बेकार बना रहा है। इस लिए मुल्क में बेकारी है। हर देश में ऐमप्लायड और अनऐमप्लायड दो तरह के लोग होते हैं लेकिन हमारे मुल्क में अपोजीशन की वजह से लोग अनऐमप्लायेबिल हो गये हैं। जिन्हें किसी काम पर नहीं रखा जा सकता। सिवाय इसके कि वह कोने-कोने में जाकर सत्याग्रह करें। इसके सिवाय वह कुछ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में अपोजीशन वाले कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करना

चाहते । यह बदकिस्मती की बात है । क्योंकि इंगलैंड और अमरीका में जहां कहीं डेमोक्रेसी है और अपोजीशन पार्टीज हैं इलेक्शन के बाद मुल्क की जिम्मेदारी सम्हालने के लिये अपने आपको उतना ही जिम्मेदार समझती हैं जितनी गवर्नमेंट अपने आप जिम्मेदार करार देती है । यह दुःख की बात है क्योंकि अपोजीशन के पास रोजाना लोगों को बरगलाने के सिवाय और कोई बात नहीं है । चूंकि यह डेमोक्रेसी है इसलिए पांच साल बाद एक दफा इलेक्शन होता है । पांच साल के बाद एक साल या 6 महीने पहले लोग जनरल इलेक्शन का प्रोपेगेन्डा शुरू कर सकते हैं । लेकिन यहां बदकिस्मती यह है कि जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है उसी दिन से लोगों को उभारा जाता है । अगर हजार, पांच सौ आदमियों को ला कर जनसंघ वाले सत्याग्रह करायें तो उसका मतलब क्या है । क्या जनसंघ के पीछे सिर्फ हजार, पांच सौ लोग ही हैं ? जब मैं यह बात कह रहा हूं तो अपनी कांस्टीट्येंसी की तरफ से कह रहा हूं । आठ लाख वोटर्स की तरफ से कह रहा हूं कि अगर दो सौ, चार सौ आदमियों को ला कर पार्लियामेंट के सामने में डेमांस्ट्रेशन करूं तो उसका यह मतलब है कि मेरे पीछे 8 लाख लोग नहीं हैं, सिर्फ दो सौ, चार सौ लोग हैं । इस तरह मुल्क में जो बेकार लोग हैं वह जनसंघ के पीछे जा कर मुल्क में एक तमाशा बनाते हैं ।

हमारे मुल्क में लोगों के पास काम करने की काफी गुंजायश है और हर आदमी काम कर सकता है । हमारे पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है पांच सौ नदियां हैं जो साल के 12 महीने बहती हैं । यहां जितने लोग हैं, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब पंजाब के भाइयों के बारे में कह चुके हैं, हर आदमी मेहनत करता है और वहां कोई आदमी बेकार नहीं है । उन इलाकों में जहां अपोजीशन वालों की एक्टिविटीज ज्यादा है बेकारी ज्यादा फैली हुई है । इस वास्ते अगर अपोजीशन वाले अपनी जिम्मेदारी को कबूल कर लें तो मुल्क की बेकारी खत्म हो सकती है ।

दूसरा सुझाव था मिली जुली हुकूमत बनाने का । जनसंघ की मिली जुली हुकूमत बार-बार बन चुकी है और हर प्रौविन्स में तीन, चार बार बन कर फेल हो चुकी है । पहले श्री राजगोपालाचारी कहा करते थे कि अगर एक अच्छी वोट के साथ एक लीकी वोट जोड़ दी जाय तो अच्छी वोट भी डूब जाती है, इस लिये अपोजीशन का कोई आदमी कांग्रेस की हुकूमत में नहीं लिया जा सकता । क्यों कि एक आइडियल के ऊपर गवर्नमेंट बनाई जाती है । हम कल ही देख चुके है कि पूरे मुल्क के लोग यह चाहते हैं कि यहां पर जो आमदनी होती है बड़े बड़े लोगों की उस को उनसे लेकर दूसरी देश हित की चीजों में लगाई जाय । एक आदमी उसे न रख सके । उस में जनसंघ वाले और स्वतंत्र पार्टी वाले लोगों ने मुखालफित की और उसके लिए अमेंडमेंट लाये । ऐसे लोगो को लेकर किसी मुल्क में क्या कोई सरकार चल सकती है ?

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : हम पार्टी की बात यहां न उठायें क्योंकि यह हिन्दुस्तान की एक बड़ी भारी समस्या है । इस पर यह कह कर मजाक नहीं करना चाहिये कि अपोजीशन रेस्पोंसिबिल नहीं है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मेरा यह तजुर्बा रहा है कि अपोजीशन रेस्पांसिबिल नहीं है ।

श्री भारत सिंह चौहान : अपोजीशन रेस्पांसिबिल रहा है । आप क्या बात करते हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अपोजीशन का रोल कैसा रहा है यह मैं बताता हूं । बंगाल में फैक्टियां बहुत हैं । श्री बी० सी० राय के जमाने में वहां पर कैपिटा इन्कम हायेस्ट इन दि कन्ट्री थी । अपोजीशन वाले लेबर को

[श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी]

उचका-उचका कर काम पर जाने से रोकते हैं और इसलिये आज उसकी पर-कैपिटा इन्कम कम हो गई है।

DR. KARNI SINGH : The Hon. Member had been in the Opposition until two days ago. He had a public mandate as an Opposition Member. Then why are you blaming us ?

SHRI RAJ BAHADUR : He is an Hon. Member of the ruling party now. He was returned on that ticket.

SHRI M RAM GOPAL REDDY : In my whole career, I was never a Member of any party except the Congress Party. If at all, I was there as an Independent, and supporting the Congress.

MR. CHAIRMAN : You may speak on the Bill.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : There are unemployed people in the country.

मैं यह बताना चाहता हूं कि लोग अन-ऐमप्लायड क्यों होते हैं। अपोजीशन वाले यह चाहते हैं कि लोगों को अनऐमप्लायड बनाकर उन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ उभार कर मुल्क में ब्लडी रेवोल्यूशन लायें। जन संघ वाले भाई इस तरह की बातें करते हैं, यह ताज्जुब की बात है।

दूसरी बात यह है कि इस देश में यह कहा जाता है कि देश में अगर यह मसला सुधर नहीं पाता है तो मिली जुली सरकार बनाई जाये। मैं कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में जनसंघ के साथ या और किसी पार्टी के साथ कांग्रेस का मेलजोल नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस का जो आइडियल है वह बिल्कुल अलग है। मुल्क में जो बेचारे अनऐमप्लायड है उनका अनऐमप्लायमेंट अगर खत्म होना है तो अपोजीशन पार्टी वाले पांच साल तक खामोश रहें क्योंकि पांच साल तक के लिये वोटर ने हमें वोट दिया है, हमें मैनडेट दिया है। मुल्क की डेमोक्रेसी को हाथ में लेकर उसे चलाने का मौका दिया है। अब हम अपनी मर्जी से हुकूमत कर रहे हैं, पाँच साल के बाद फिर हमें वोटर के पास जाना होगा। तो आप जरा इस पर विचार कीजिये, रोज-रोज पार्लियामेंट के सामने इस किस्म का डिमान्स्ट्रेशन करने से मुल्क में अनएम्पलायमेंट बढ़ता है और उसकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, इन सब लोगों पर है, कांग्रेस पर नहीं है।

आज दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे देश जो अनएम्पलायमेंट ज्यादा है, उसका एक कारण पाकिस्तान भी है। लाखों-करोड़ों लोगों को पाकिस्तान से मार-मार कर हमारे मुल्क में भेजा जा रहा है। हर साल करोड़ों लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं यह हमारी बदकिस्मती है। इस लिये अनएम्पलायमेंट के लिये सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देने से काम नहीं होगा। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी मुल्क है, उसके साथ हिसाब-किताब किया जा रहा है अगर वह पूरा हो जायेगा तो बहुत सारा अनएम्पलायमेंट खत्म हो जायेगा।

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगांव) : पीठाधीश जी बेकारी की समस्या जितनी कठिन है, उतनी कष्टदायक भी है और किसी लोक-तंत्रीय देश में अगर बेकारी है और उसका समाधा शीघ्रता के साथ नहीं होता है तो यह एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह देश के सामने उप-स्थित होता है। मैं अगर इसको अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखूं तो 370 करोड़ लोग सारे संसार में हैं और उसमें भी 100 में से 70 लोग एशिया और अफ्रीका के भाग में रहते हैं। केवल 30 उन देशों में रहते हैं जो गोरे लोगों के देश हैं। सारी समृद्धि विज्ञान का विकास, तकनीकी ज्ञान, सम्पत्ति का अर्जन और परम्परा-गत कालोनियल पावर्स के द्वारा जो एशियाई और अफ्रीकी देशों का एक्सप्लायटेशन हुआ,

उसके माध्यम से वे समृद्धशाली हो गये, हम पिछड़ गये और इसी सन्दर्भ में हमारा देश भी पिछड़ गया। जितना औद्योगीकरण हमारे देश में होना चाहिये था—23 वर्षों में, अगर मैं यह कहूं कि बहुत कुछ हुआ है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, लेकिन इसके लिये 23 वर्ष ही काफी नहीं हैं। हमारा जो पिछला इतिहास है, उसको भी देखना होगा, जब दुनिया के देश आगे बढ़ रहे थे, संसार आगे बढ़ रहा था, हम कालोनियल पावर के नीचे उतना नहीं बढ़ रहे थे। उस समय हमारी यह जनसख्या 40 करोड़ थी...

सभापति महोदय : ईम्पीरियल पावर के नीचे।

श्री राम सहाय पांडे : जी हां, इम्पीरियल पावर के नीचे। 1904 की बात है एक सेन्सस हुआ था, तो उस समय हमारी आबादी करीब 25 करोड़ थी, लेकिन आज 60 करोड़ है और 1960 में हमारी आबादी 90 करोड़ हो जाएगी। यह प्रश्न धरती से, वातावरण से, साधनों से, साधनों के समन्वय से सरकारी प्रबन्ध से और नैसर्गिक काम करने की प्रवृत्ति से सम्बन्ध रखता है। इन सब का समन्वय करना पड़ेगा। आज जितने हमारे पास साधन हैं—जैसे भोजन का सीधा प्रश्न है, पर-कैपिटा इन्कम का सीधा प्रश्न है, काम का सीधा प्रश्न है, बेकारी का प्रश्न है, उसमें भी जो गांव के लोग बेकार हैं, उनका अलग प्रश्न है और जो लोग शहरों में बेकार हैं उनका अलग प्रश्न है। जिनके पास धरती नहीं है, उनके बेटे बेकार हैं, उनका अलग प्रश्न है। जिनके पास धरती है, जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके बेटों का अलग प्रश्न है, फिर वही लोग जब शहरों में जाते हैं तो उनका अलग प्रश्न है। इन सबका तालमेल यदि राष्ट्रीय स्तर पर करें तो मुझे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। क्या कोई ऐसा दिन आएगा कि हम—यह ठीक है कि अपने संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज में हमने बहुत सारी बातें कही हैं और यह भी कहा है कि समता और एकता के नियम पर काम देंगे, सब कुछ करेंगे—लेकिन यह एक बड़ा भारी प्रश्न है, आर्थिक प्रश्न है, काम का प्रश्न है, औद्योगीकरण के माध्यम से, खेती के माध्यम से, छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के माध्यम से हम एक बड़ी परिकल्पना करें, उड़ान भरें, तब भी यह प्रश्न सामने आता है कि क्या आबादी की बढ़ोत्तरी को देखते हुए, देश के सीमित साधनों को देखते हुए, यह सम्भव है। देश की आबादी बढ़ रही है, लेकिन धरती नहीं बढ़ रही है। 40 करोड़ एकड़ धरती हमारे पास है, जिस पर खेती होती है, आबादी 60 करोड़ है. एक पर डेढ़ का बोझा है। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय संख्या को देखें तो संसार की जनसंख्या को देखते हुये 100 में 60 भूखे हैं और उन 60 में भी 10 भारतीय हैं और और इस 10 का अनुपात लगायें तो 22-23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा स्क्वेयर-मील नहीं मिलता है। एक तरफ भोजन, फिर काम, काम के अनुसार उसकी औसत आमदनी, फिर रहन-सहन का प्रबन्ध, ये सब इतने कठिन काम मालूम पड़ते हैं कि चाहे हमारी सरकार हो या कोई सरकार हो, यथार्थ क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, साधन क्या हैं, साधनों समन्वय क्या है, जिस गति से आगे चलना है, उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं।

इसका एक कारण ब्यूरोक्रेसी है। नेताओं का काम है—योजना बनाना, सोचना, मेंडेट प्राप्त करना, जनता की स्वीकृति लेना, यह सब ठीक है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने का माध्यम ब्यूरोक्रेसी है जिनके माध्यम से हम उसको कराना चाहते हैं, वह नहीं हो पाता है। एक फाइल के एक टेबिल से दूसरे टेबिल तक जाने में एक महीना लग जाता है। देश में आज जो जनजागरण है, उत्साह है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, उसमें तेजी आये, इसी सन्दर्भ में मैं इस बात को कह रहा हूं। हमारे लोग तेजी से काम करें, जिस गति से समय आगे बढ़ रहा है

[श्री राम सहाय पाण्डे]
उसी गति से आगे बढ़ें तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जांय। जब हम देखते हैं कि काम नहीं हो रहा है, सरकार के काम को ही ले लीजिये, उसकी मशीनरी को ले लीजिये, मूव नहीं करती है, चलती नहीं है, उसमें गति नहीं है, शक्ति नहीं है, एक बड़ी भारी उदासीनता है, चाहे इसके कोई कारण हों, तो मन को क्षोभ होता है। हमें इसका अनुसन्धान करना चाहिये, कि इसका क्या कारण है, क्यों आगे नहीं बढ़ रही है।

मैं पिछले दिनों साउथ-ईस्ट-एशिया गया था। मैंने थाईलेंड में देखा कि पिछले 10 वर्षों में कितनी प्रगति हुई है। वहां चावल की खेती होती है खूब चावल पैदा किया है। मैंने मनीला में देखा, काफी उद्योग बढ़े हैं काम बढ़ा है और उन्होंने अपने यहां की बेकारी को दूर किया है। यूरोप को छोड़ दीजिये, वहां तो मैन-पावर की शार्टेज है, आदमियों की कमी है। हमारे यहां डिमाण्ड और सप्लाई की दृष्टि से मैन-पावर की सप्लाई ज्यादा है और काम कम है। इकानामिक दृष्टि से देखें तो भी डिमाण्ड कम है, सप्लाई ज्यादा है। इसलिए संसार भर में मनुष्य की सबसे कम कीमत, सब से कम गरिमा, प्रेस्टिज, सबसे नीचे स्तर का मनुष्य हमारे देश में है. ऐसे ही मिलते जुलते कुछ और देश भी हैं, जो गरीब हैं, लेकिन वे सब एशिया में हैं। उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। परम्परा से भी हमारे समाज में काम की कोई वैल्यू नहीं कही गई है। एक लड़का किसी प्रकार से मेहनत करके जूते की पालिश का काम करके अर्जन करता है तो उसके स्वालम्बन की प्रशंसा समाज नहीं करता है, उसको सामाजिक सम्मान प्राप्त नही होता है। उसके काम की गरिमा और प्रतिष्ठा को कभी विवेक से आंका नहीं है, कभी पुरस्कृत नहीं किया, सम्मानित नहीं किया। उसके काम को छोटा काम कहा जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप काम की गरिमा को बढ़ाइये, उनमें तालमेल जोड़िये। कोई व्यक्ति कोई भी काम करे, उसके माध्यम से उसको सम्मान दीजिये, तब कुछ लोग उन कामों की तरफ प्रभावित होंगे। हमारे यहां एक समाज है, जिन में ब्राह्मण और क्षत्री आते हैं, जो अपने आपको ऊंचा समझते हैं, उनसे कहिए कि आप जूता-पालिश का काम करें, मोटर सफाई का काम करें, वर्कशाप में काम करें, तो वे नहीं करेंगे। वे इस भावना से पीड़ित है कि हम तो इतने बड़े परिवार के लड़के हैं, ऐसा काम कैसे करें। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिये। नीचे के लोगों को उठाइये ताकि काम की गरिमा बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, उनको नीचे से ऊपर लाइये ताकि कामों का तालमेल ठीक से हो सके।

मेरा ऐसा ख्याल है कि हम रे पास जितनी धरती है, पानी और खेती के साधन हैं, इन सब का समन्वय हो, तो कम से कम गांवों के बच्चों को सम्भाला जा सकता है। आज हो यह रहा है कि वे पढ़-लिख कर शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, अगर यहां पर सिंचाई का इन्तजाम हो जाय तो उनका शहरों की तरफ दौड़ना रुक सकता है। बेकारी के प्रश्न का यह अर्थ नहीं है कि उनको नौकरी ही दी जाय, बेकारी से नौकरी का सम्बन्ध तोड़िये, स्वालम्बन की दृष्टि से नौकरी नहीं, बल्कि व्यवसाय, श्रम के माध्यम से काम, काम के माध्यम से उत्पादन की परिकल्पना से देश को उठायेंगे, तब देश उठेगा।

आप इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कीजिये—देश के सारे साधनों को प्रायोरिटी के आधार पर किसानों को दीजिये, और कहिये कि हम सिंचाई के साधन देते हैं, तुम यहां पर काम करो, सिंचाई के बाद छोटे-छोटे उद्योगों के लिये बिजली दीजिये, एप्रोच रोड्स दीजिये, ताकि बिक्री के माध्यम से लाने और ले जाने में सम्बन्ध स्थापित हो सके। छोटे-छोटे उद्योग दीजिये—गांधी जी की जो कल्पना थी, अगर आप यह करेंगे तो वहां के लोग वहीं खप जाएगे,

वहीं रह जाएंगे और इस नये औद्योगीकरण के क्षेत्र के नीचे विकास पाएंगे, प्रकाश पायेंगे, जब हम ऐसा प्लानिंग करेंगे, तब ही कुछ हो सकेगा।

आप दिल्ली को देखिये—ऐसा मालूम पड़ता है कि मैनहैटन है, बम्बई न्यूयार्क बन गया है। अरबों रुपया आपने इनके ऊपर खर्च कर दिया है। अब इनके विकास के लिये, बड़े-बड़े भवनों को बनाने के लिए पैसा न दीजिये, बल्कि जो लोहा और सीमेंट आप यहां के बड़े-बड़े भवनों को बनाने पर खर्च करते हैं, उसको उठा कर देहातों में ले जाइये, जहां आदमी अनाज पैदा करता है, सारे साधन पैदा करता है, जिनकी बदौलत अर्बन एरियाज की इकानमी चलती है, सारा पैसा खिंच कर उनकी तिजोरियों में चला जाता है। सारे धनी धनी होते जा रहे हैं और गरीब, और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। हमको यह क्रम तोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपने गांवों को सब सुविधा प्रदान कर दें तो फिर गांव का कोई लड़का शहर की तरफ नहीं आयेगा। इस तरह से आप अपने आर्थिक ढांचे को एक नई दिशा देकर, पुरानी व्यवस्थाओं और मान्यताओं को तोड़ कर, गांवों को सम्भालिये। शहरों को छोड़ दीजिये, उनके लिये बहुत कुछ हो चुका है, अरबों रुपया उन पर लग चुका है, बड़े-बड़े अस्पताल, कारखाने, बड़े-बड़े भवन बन चुके हैं। आप दिल्ली को देखिये—पैराडाइज बन गया है, सुन्दर-सुन्दर फब्बारे चल रहे हैं, एक तरफ तो पीने के लिये पानी नहीं है, पांच करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलता है—यह कैसी नादानी और बेवकूफी से भरी हुई बात है। हमारे प्लानिंग कमीशन ने पिछले 20 वर्षों से इस दिशा में क्यों नहीं सोचा कि गावों में साधनों की ज्यादा जरूरत है। गांवों में हमारा किसान रहता है, जो इस देश की रीढ़ है, आज तक हम उसको दुतकारते रहे, यह चीज अब नहीं चलेगी। गांवों में सारे साधन श्रोतों की गंगा बहा दीजिये, फिर वे शहर की तरफ नहीं आएंगे और इस तरह से इस प्रश्न का समाधान हो सकेगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, बेकारी की समस्या हमारे देश में बहुत ही विकराल और दिन प्रति दिन भयंकर होती जा रही है। आज देहातों में लोग बेकार हैं। शहरों में बेकार हैं और पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है कि अभी तक सरकार के पास कोई सही आंकड़े नहीं है कि कितने लोग हमारे देश में बेकार हैं। यों इस सदन में इस सवाल को बार बार उठाया गया है और बराबर सरकार ने यह उत्तर दिया है कि समिति बिठाई गई है और उसका प्रतिवेदन आने पर सही तसवीर देश के सामने रखी जा सकेगी कि हमारे देश में बेकारों की संख्या क्या है। आजादी के इतने दिन गुजर गए लेकिन हम बेकारों की संख्या का सही सही पता भी नहीं लगा पाये गोकि सभी कहते हैं कि हमारे देश में बेकार लोगों की संख्या करोड़ों में है। संविधान में यह कहा गया है कि हम तमाम लोगों को काम देंगे, नागरिकों को काम देंगे, उनको जीने लायक मजदूरी देंगे, जहां वे काम करते हैं कारखानों में या खेतों में उनके काम करने के तरीकों में सुधार करेंगे ताकि उन्हें काम करने में आसानी हो सके। हम कहां तक इस दिशा में आगे बढ़े हैं इसको हम सभी जानते हैं। यह सही है कि हम आगे बढ़े हैं लेकिन बेकारी उस से कहीं ज्यादा और कई गुना आगे बढ़ गई है। हर योजना के काल में कुछ न कुछ काम तो जरूर लोगों को मिलता है। लेकिन बेकारों की पलटन उससे कई गुना अधिक बढ़ जाती है। यह हालत आज चौबीस साल की आजादी के बाद भी हमारे देश की है। हमारे देश के 41 प्रतिशत देहातों में रहने वाले लोग बिना जमीन के हैं। उन्हें आप जमीन भी नहीं दे सके हैं और इस तरह से उनमें कुछ हद तक बेकारी भी आप दूर नहीं कर सके हैं। आप उनके लिए रोटी की व्यवस्था भी नहीं कर सके हैं। शहरों में लाखों करोड़ों लोग मारे मारे फिर रहे हैं नौकरी की खोज में। रोज असेम्बली और पार्लियामेंट के

[श्री रामावतार शास्त्री]

मेम्बरों के पास दर्जनों लोग पहुंचते हैं यह प्रार्थना लेकर कि हमें नौकरी दिलवा दीजिए। एम. ए. और बी. ए पास लोग चपरासी की नौकरी खोजते फिरते हैं, बूट पालिश करते फिरते हैं इस वास्ते कि उनको कोई काम नहीं मिलता है। यह भयंकर स्थिति हमारे देश में तब विद्यमान हैं जबकि हमने संविधान में वादे किये हैं और यह निश्चित किया है कि हम इन तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे।

अभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसलिए किया गया है कि बैंकों पर पूंजीपतियों का जो एकाधिकार है, उसको समाप्त किया जा सके, खुद के लिए जो वे पैसों का इस्तेमाल करते हैं, उसको रोक सकें, बैंकों में जो जनता की राशि जमा है, उस राशि का इस्तेमाल हम रोजी बढ़ाने में, बेकारों को काम देने में कर सकें, किसानों को कर्जे दे सकें ताकि वे उपज बढ़ा सकें, सिंचाई की व्यवस्था कर सकें। हिन्दुस्तान की जनता ने बहुत शानदार समर्थन आपको प्रदान किया इस वास्ते कि हमारे देश के कुछ प्रतिगामी लोगों ने, देश को आगे बढ़ने से रोकने वालों ने उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की। उस सबके बावजूद इस सदन ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने संबंधी बिल को पास किया और जनता में एक नई आशा जगी। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या बेकारों को आपने कर्जे दिये? अभी हाल में मैंने एक सवाल पटना और बिहार के बारे में किया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से बेकार स्नातकों को कितने कर्जे दिये गये। इसका जवाब मुझे यह मिला कि इसकी सूची हम नहीं रखते हैं। सूची नहीं रखते हैं तो कैसे आप कर्जे देते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। इसका साफ मतलब यह था कि असलियत को आप छिपाना चाहते थे। बेकारों को कर्जे नहीं दिये जाते हैं। आज भी 75 प्रतिशत कर्ज हिन्दुस्तान के एकाधिकारपतियों को, पूंजीपतियों को दिये जा रहे हैं। क्या इस तरह से बेकारी दूर होगी? टाटा, बिड़ला डालमिया आदि जो हिन्दुस्तान के 75 पूंजीपति परिवार हैं और जिन्होंने हमारे देश को और इसके जीवन को अपनी गिरफ्त में कर रखा है, अपने अंकुश में फंसा रखा है उन्हींको अगर कर्जे दिये जायेंगे तो क्या बेकारी दूर होगी? क्या उन्हीं का सहारा लेकर बेकारी को दूर किया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। बैंकों के पैसे का इस्तेमाल बेकारों को कर्जे देने में, छोटे छोटे उद्योग धन्धे बढ़ाने में आप करिये ताकि ज्यादा से ज्यादा काम धंधे देहातों में खुलें। साथ ही साथ शहरों में छोटे-छोटे उद्योग धधे बढ़ें। जब ऐसा होगा तब जाकर शहरों में भी बेकारों को काम मिलेगा और देहातों में भी मिलेगा। इंजीनियर जो बेकार हैं, उनको आप कर्जे दें, दूसरे जो शिक्षित हैं और अशिक्षित भी हैं, उनको आप कर्जे दें।

जनसंघ के श्री चौहान ने अपने बिल पर बोलते हुए कहा है यह कि काम नहीं हो रहा है और 1976 की इलेक्शन तक नहीं होता है तो राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा बना दिया जाए और वह टेलेंट खोजेंगे स्वतंत्र पार्टी में, जनसंघ में और पता नहीं कहां कहां और तब वह जो सरकार बनायें, वह इसको हल करे इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में आज जनतंत्र जो फल फूल रहा है, पल्लवित हो रहा है, इसको भी वह खत्म कर देना चाहते हैं और सारी ताकत राष्ट्रपति को सौंप देना चाहते हैं क्या इससे समस्या का समाधान होगा? बहुत से देश हैं जहां डिक्टेटरशिप है। बगल में पाकिस्तान है जहाँ याह्या खां ने सारी शक्तियाँ हथियाली हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहाँ बेकारी की समस्या का समाधान हो गया है? राष्ट्रपति को सारे अधिकार दे दिये जाते हैं तो क्या सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है? किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि उसको घुमाया और एक दिन में सब को काम मिल गया, जीने लायक मजदूरी मिल

गई, सभी समस्याओं का देहातों और शहरों में समाधान हो गया, जमीन का बंटवारा हो गया, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, सारे काम हो गए। समस्याओं को हल करने का यह तरीका नहीं है, इसलिए मैं बिल का समर्थन नहीं कर सकता हूं। बेकारी दूर करने का रास्ता यह है कि आप मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था के घेरे में से निकलिये। आजादी के बाद आपने जो हिन्दुस्तान में पूंजीवाद को विकसित करने का रास्ता अपनाया है, नीति अपनाई है उसको आप छोड़िये। जो बड़े बड़े उद्योग हैं और जिनपर पूंजीपतियों का एकाधिपत्य है, उनको अपने कब्जे में करिये। चिल्लाने दीजिये जनसंघ के लोगों को, स्वतंत्र पार्टी के लोगों, को हिन्दुस्तान की प्रतिगामी शक्तियों को, राजा महाराजओं को। उनकी आप चिन्ता न करें। सचमुच अगर आप चाहते हैं कि बेकारी दूर हो, लिविंग वेज उनको मिले, दूसरी समस्याओं का समाधान हो तो आपको वर्तमान स्थिति में से निकल कर समाजवाद के रास्ते पर चलना होगा जो भी बहुत दूर की बात है। लेकिन जनतांत्रिक एवं प्रगतिशील ताकतें मजबूत हों, उसकी नीव मजबूत हों यदि आप यह चाहते हैं तो वर्तमान पूंजीवादी समाज को आप तोड़िये। समाजवाद का नारा लगाने से समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। हिन्दुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब जनता अपने संघर्षों के जरिये आगे बढ़ेगी, समाजवाद लाएगी और उनके संघर्ष की बदौलत आपको संविधान संशोधन बिल लाना पड़ा और उसको पास करना पड़ा। उसी की बदौलत आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसी की बदौलत आप जमीन में सुधार करने की बात, सीलिंग की बात कर रहे हैं। 23 साल तक आप बैठे रहे। लेकिन अब आप बैठ नहीं सकते हैं। जनता आपको बैठने नहीं देगी। बेकारी की समस्या के समाधान के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके गैर पूंजीवादी व्यवस्था के रास्ते पर आप चलिये और तमाम सम्पत्ति का, तमाम उत्पादन के साधनों का आप राष्ट्रीयकरण करके आगे बढ़िये। जब आपने ऐसा किया तभी आपको रास्ता मिलेगा। गरीबों को आप जमीन दो। लैंड सीलिंग आप करो। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने जो रिपोर्ट दी है उस पर विचार करके उसको लागू करो। तब देहातों की 4। प्रतिशत जनता को काम मिलेगा और शहर के लोगों को भी काम मिलेगा। बैंकों को आप कसिये ताकि 75 प्रतिशत जो कर्जा पूंजीवादियों को वे दे रहे हैं उसको न देकर गरीब किसानों को, मध्यम वर्ग के किसानों को, बेकार नौजवानों को बेकार स्नातकों को और छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वालों को दें। यह रास्ता है बेकारी को दूर करने का।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं कि इस बिल के द्वारा सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में दे कर हिन्दुस्तान के जनतंत्र को ये मटिया मेट करना चाहते हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्य ने यह बिल रखा है, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि लोकतंत्र के कारण वह इस सदन में बैठे हुए हैं और इस बिल के द्वारा वह लोकतत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि अगर सरकार 1976 तक देश के लोगों को काम और उचित मजदूरी आदि न दिला सके, तो राष्ट्रपति सब टेलेन्ट्स को इकट्ठा करके एक सरकार बनायें। उन्होंने कोई चुनी हुई सरकार बनाने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान के बुद्धि वाले लोगों को इकट्ठा करके देश का शासन चलाया जाये।

आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है :

> "In this part, unless the context otherwise requires, "the State" includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or

[श्री मूल चन्द डागा]

other authorities with the territory of India or under the control of the Government of India."

दिल्ली में कई सालों से जनसंघ का शासन है। और भी कई राज्यों में जनसंघ सरकार में शामिल हुआ है। वे भी 'स्टेट' के अन्तर्गत आ जाते हैं। शायद माननीय सदस्य यह समझते हैं कि लोकतंत्र के द्वारा उनकी पार्टी सरकार में नहीं आ सकती है और कांग्रेस का शासन नहीं जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को सरकार में लाने के लिए एक दूसरा दरवाजा ढूंढा है। लेकिन इस तरह वह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वह जानते हैं कि चाहे बंगाल में हो या पंजाब में राष्ट्रपति का शासन कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। फिर भी वह यह बिल लाए हैं कि 1976 के बाद लोकतंत्र की समाप्ति कर दी जाए और राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाये। जैसा कि मैंने कहा है, माननीय सदस्य की भावना और इच्छा ठीक हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो उपाय रखा है, वह ठीक नहीं है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज हमारे देश में करोड़ों लोग बेकसी और विवशता के कारण बेकार हैं। हमने इतिहास में पढ़ा है कि एक जमाने में हमारे देश में ऐसे राजा थे, जो प्रजा में घूम कर देखते थे कि कोई आदमी भूखा तो नहीं सोता है, कोई बेकार तो नहीं है, कोई पीड़ित तो नहीं है और इस प्रकार अपनी प्रजा की सेवा में दिन-रात काम करते थे।

आज भी शासन की यह जिम्मेदारी है कि जो काम करना चाहता है, उसको काम दिया जाये। आर्टिकल 41 के अनुसार शासन पर लोगों को काम देने का उत्तरदायित्व डाला गया है। हम इस उत्तरदायित्व को टाल नहीं सकते हैं। चौबीस साल के हमारे शासन के बाद भी बेकारी का रोग हमारे देश की जड़ों को कमजोर कर रहा है। यह ठीक है कि सरकार ने मिनिमम वेजिज एक्ट लागू किया है, समाज-कल्याण की योजनायें चलाई हैं और गरीबों को कुछ ऊंचा उठाया है। लेकिन अब तक हम पढ़े-लिखे और अन्य बेकार लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। जब हम लोकतांत्रिक समाजवाद का नारा लगाते हैं, तो हमें इस देश में लोगों को काम और रोजगार देने की व्यवस्था करनी ही होगी।

"Social welfare means to secure health and whole development of the society by enabling the backward, weak, under-developed and handicapped limbs (individuals and groups) to stand abreast with human society as a whole so as not to impede the general progress and development of society as a whole."

यह सब समाज और शासन का कर्त्तव्य है। अनएम्पलायमेंट के कारण देश की प्रगति में रुकावट पड़ती है, देश आगे नही बढ़ सकता है, बल्कि पीछे जाता है। इसी कारण कई देशों में खूनी क्रान्ति होती है। इसी कारण हमारे देश में नक्सलाइट्स पैदा हुए हैं।

मैं समझता हूँ कि एक तरह से यह बिल सरकार के लिये एक चेतावनी है। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि स्टेट लोगों को काम आदि देने के लिए प्रयास—"एनडेवर"—करेगी। आखिर सरकार कब तक एनडेवर करती रहेगी? आज हम देखते हैं कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है और सरकारी नौकर के बेटे को सरकार में नौकरी मिल जाती है। इसको बन्द करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उस घरके किसी सदस्य को रोजगार दिया जाये और जिस परिवार में कोई कमाने वाला है, जो परिवार इनकम टैक्स देता है, उसके किसी सदस्य को काम न दिया जाये।

आर्टिकल 41 और 43 की मंशा यही है कि हम लोगों को काम और लिविंग वेज देने का वादा करते हैं। 'गरीबी हटाओ' का नारा कोई छलावा नहीं है। हमको गरीबी हटानी

होगी, या हमको हटना होगा। अगर हम में मजबूत इरादा, डेटरमिनेशन और निश्चय है, तो गरीबी हटेगी। आज कई सालों के बाद सीलिंग की बात की जा रही है, मिनिमम वेजिज एक्ट पास किया गया है, लेबर लाज पास किये गये हैं, बेकारी को दूर करने के लिए क्रैश प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसके लिए पचास करोड़ रुपये दिए गये हैं। यह सब ठीक है, लेकिन बेरोजगारी को दूर करना लोकतांत्रिक समाजवाद का पहला कर्त्तव्य है। फ्रांस के कांस्टीट्यूशन में भी कहा गया है :

"The nation ensures to the individual and the family the condition necessary to their development. It guarantees to all, and notably to the child, mother and the aged workers protection of health, material security and a rational religion."

यू० एस० एस० आर० में भी यही स्थिति है।

माननीय सदस्य ने अपने बिल में जो सारे टेलेंट्स की सरकार बनाने की बात कही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन उन्होने 1976 तक लोगों को काम देने की जो बात कही है, उससे मैं सहमत हूं। अगर वह इससे भी पहले का समय रखते, तो ज्यादा अच्छा होता। इस बारे में कोई टाइम-बाउंड प्रोग्राम होना चाहिये। जितनी भी पंच-वर्षीय योजनायें चलाई गई हैं, उनमें बेकारों की संख्या बढ़ी है।

इस देश में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, जिन्होंने मां-बाप की दौलत खर्च की है, आज वे बेकार हैं। आज इस देश में बेकारी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसको मिटाने के लिये मजबूत कदम उठाये जाने चाहिये। माननीय सदस्य चाहते हैं कि हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिये गये हैं, उनके अनुसार काम करना चाहिये। इसी को दृष्टि में रखकर हमने कल एक प्राग्रेसिव लेजिस्लेशन पास किया है। हमारा इरादा है दौलत वालों से दौलत लेकर राष्ट्र के काम में लगाई जाये और गरीबों को ऊंचा उठाया जाये।

माननीय सदस्य चाहते हैं कि टेलेन्टिड लोगों की सरकार बनाई जाये और राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाये। यह बात लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। हम इस भावना को पसन्द नहीं करते हैं। हां, हम इस बात से सहमत हैं कि बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिए एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। इस बारे में किसी बहाने से काम नहीं चलेगा। केवल प्रयास का प्रश्न नहीं है। हमको ठोस काम करना होगा और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इसके परिणामों का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होगा।

DR. KARNI SINGH (Bikaner) : Mr. Chairman Sir, only yesterday what the hon. Member termed as a very progressive Bill was passedby this hon. House and nearly everybody spoke about the poor people and their lot. Today the Bills have been introduced in this House by hon. Shri B. S. Chauhan and myself that deal with unemployment and it is a matter of great regret that from the ruling Party so little interest has been shown and the House is virtually empty.

16.41 hrs.

[SHRI N. K. P. SALVE *in the Chair*]

I only hope that the ruling Party genuinly believes in eradicating poverty and that they are not only poor table thumpers when it comes to getting credit for some sort of legislation that is passed in this House.

You know, Sir, that in 1953 or 1952 the Hon'ble Mr. A. K. Goapalan had introduced a Resolution on unemployment and had spoken on that occasion. Since then this question has been brought before this House over and over again and I feel that instead of this hon. House going on to blaming Jan Sangh, Swatantra or any other opposition party, why not come to grips with the situation. It may be the Congress who is in power today. It may be the Communists who will come into power tomorrow-which is almost sure-then this major problem

[Dr. Karni Singh]

which is affecting our country will have to be solved. Merely to say because the Bill was brought in by a Jan Sangh Member or an Independent Member therefore it does not merit attention, I do not think that is very fair.

As regards the question of population increase as Mr. Pandey had just mentioned—could not agree with him more—I think I wa s one of the younger and earlier Member of this House who for the last fifteen years have been raising this point over and over again, eversince the time of Pandit Jawahar Lal Nehru that the population explosion was round the way and it would not be possible for India to provide the requisite j obs for the number of new children being born. You know fifty thousand children are born everyday. This is no secret. We also know our Family Planning programme has not succeeded as we would like it to be. The reasons are obvious. We the Members of Parliament have not got the courage to go back home and stand on the public platform and tell the people that population problem is far too serious. Very few Members of Parliament have done it. I ask the hon. Members to put their hands on their heart and ask that question : Have they spoken to the masses over and over again during the election times on this subject ? The people in this country are sometimes old fashioned and because of that a Member of Parliament is frightened to make them angry. But I am afraid this question of population explosion as the hon. Mr. Pandey said that the population of India will touch 90 crores. We all know. In fact we also know another Asian country—Japan-was able to taper off their population at 10 crores. If Japan could why not India ? If you want me to believe that Ministers in Japan are superior to ours I do not want to offer a comment on that. But I do feel that the people of India if properly approached, if the same question was put to them and their willing cooperation sought, I am sure, the population explosion could be curbed and if we are able to curb it to say: 10,000 increase a day from 50,000 increase a day I am quite sure this question of unemployment will come within the means of our solution. But as matter stands today we are only increasing poverty more and more and it does not matter how many Bills you pass in this House, you will not be able to eradicate poverty and unemployment. Therefore, I feel this matter requires very serious thought. It is no question of hurling abuses on each other—from one parr of the House and another. Whether it is the son of a Congressman who is unemployed or a Jan Sangh man who unemployed makes no difference. He is an Indian citizen and to provide job for the youth of our country is our first and foremost duty.

The Directive Principles in our Constitution have made references to providing jobs. I remember, once I made a suggestion to the hon. Shri Lal Bahadur Shastri in one of the meetings, to which he called the Opposition Members, that if the Prime Minister could make an appeal to the nation that there should be no bady for two years, instead of one crore and thirty lakhs increase in our net population every year, as a result of that appeal India's population increase might drop to, say, 25 lakhs annually. Shri Shastri said, "I myself have such a huge family ; how can I make an appeal ?" I told him than. "Sir, you are the right man, because you are the man who had suffered ; you know what a large family means in relation to your savings." When Lal Bahadur Shastri died he left nothing. He was an horest man.

I again wrote to Shrimati Indira Gandhi a year or so ago and I appealed to her that during the elections it would be advisable if she from her platform appealed to the nation that the population explosion was one of the biggest problems that world was facing, that mankind was facing ; that it was more dangerous to mankind than the hydrogen bomb. The Prime Minister wrote back and said that she agreed. But I would like to know in how many public utterances she made this as her primary objective. If you talk about eradicating poverty, the increase in population is entirely a tied-up question.

Now, you look at your family planning programmes. I have served on these committees and I have spoken to the people in the Family Planning Council. They have this very poetic slogans about you should not have more than two or three children, *aur uske bad bas.* I told them, for God's sake tie up your slogans with employment and hunger. If the man-on-the-street sees a slogan on a wall or a hoarding and if he realises that that meant something much more to him, because it meant the employ-

ment of his children, it meant whether he could give his children a fair square meal, he would be able to respond to that much more than to the beautiful pictures on the wall with very musically sounding slogans. I am afraid, the family planning programme still goes on with those beautifully sounding slogans and the result is that your population increase is one crore and thirty lakhs ; the result is that not only we but our children and our children's children will not be able to solve this problem of population explosion and consequently the problems of food, hunger, housing, unemployment and *garibi*.

With that I would like to conclude my remarks. But before I conclude I would like to place one thing on the floor of this House, namely, what I said a year ago. I feel it my duty to bring it to the attention of this House that when the privy purses Bill comes up and when this House, I assume, passes it, two lakhs of people will go out of jobs. I have not heard a single pronouncement from any minister but I would like an announcement made that these two lakhs of people, who are Indian citizens and who will be on the Indian streets, will be provided with adequate jobs. I hope that such a pronouncement will be made.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam) : Mr. Chairman, it is very strange that a friend from the Jana Sangh has brought forward this Bill. And what is the remedy ? I do not know whether he means nomination of a government by the President, of all parties. But what will he do ? What is his party's programme for solving this problem of unemployment ?

We saw many governments of all these parties in several States, including his own party participating in U.P., Madhya Pradesh, Punjab and so many places. How far have they solved this problem of unemployment ?

Our friend just now said about family planning. Our friend's party does not believe in family planning. So, how are we going to solve the problem with a multiparty government ? So, that is not the solution at all. Hence, I oppose this Bill.

Yes, it is a giant problem facing this country, specially with this population explosion. There are so many young men coming out of colleges. There are so many people, men and woman, without employment. We saw the other day a number of women, educated women. In Parliament they said that only 2 per cent of the women are employed. So, this problem is a big problem facing both men and women in the country, specially the younger generation.

Apart from that, he mentioned about workers working in farms, factories and industries. To say that the result achieved is "minus" is really fantastic. That means one must be blind to the facts. To say that the progress is not so fast as we wanted it is all right. There are the limitations. After we achieved Independence, we have been building up our country. We are a country where the British ruled for 200 years and they left us without anything, almost like a house robbed by them. We had to built up our own resources. Because of the personality of Mr. Nehru, because of his goodwill abroad, we could get so many facilities and we could get so much from outside to build up our country.

When we are building up our country, what do our Swatantra Party people say ? No public undertakings ; import machinery from outside. How can we provide employment to our people ? We are creating a base for our industry in this country through our public undertakings, producing small machines for further industrial expansion. That is how we can solve the problem. That is how we can provide employment to people.

There should be more evtensive agriculture and more and more people should be employed there This is not the way of solving the problem by saying, "Government *hatao*" and all that, somebody pulling this side and that side. We have seen how "Grand Alliance" fared in the elections. We know how much confidence the people have in them in solving the problem of unemployment We were facing this problem even before going to the elections. That is not the solution at all.

Today, the people get Rs. 2, Rs. 3, as their wages. But certainly they are getting much more than what they were getting 20 years back. It is not enough because the prices are soaring up so high that the pace is slower as compared to the rise in prices.

So many States have now scrapped prohibition. At whose cost ? It is at the cost of the ordinary workers. At least 50 per cent of the amount of money that they

[Shrimati Lakshmikanthamma]

get after a day's toil is spent at the cost of their children, at the cost of their children's comforts, at the cost of their children's education, etc., and they spend it in drinking. So, the Government should see that prohibition is, once again, introduced in these States.

The Government should also take up the responsibility of providing security to the children of workers, such as, food, education, shelter and clothing The Government should provide some of the common requirements and make them feel secure in case of unemployment of the workers.

There is no half-way house to socialism. However much our friends might say, ultimately, we have to march towards a socialistic society. There is no use of merely shouting, "Unemployment *hatao*," Just like they were saying, "Indira *hatao*", they brought in another form of slogan saying "Government *hatao*". But that is not going to solve the problem.

It is only a sustained effort which will take this country towards socialism. We have to march towards socialism. We have to learn the experience of others in socialist countries as to how they have tackled and solved this problem.

Then, whenever there is a talk of cooperative farming, these friends go and confuse the farmers. Instead of educating them, they go and confuse them saying, "Your land will be taken away by somebody else." Instead of educating them and asking them to make use of the facilities of the cooperatives, this is what they do. I go to the extent of saying that we should have more and more cooperative farms. There is Government waste land in many places. We should have more and more of these landless people and put them there and have collecting arming

Coming to cottage industries, there is a demand for khadi. In foreign countries, there is a craze for khadi. There is a lot of demand for export of khadi from this country. Why not have more and more export of khadi ? But you are neglecting it and doing something hotch-potch here and there. There should be a planned effort in this direction. You can make a study in the field of cottage industries about the demand of our goods in other countries and export more and provide more and more employment to our own people here. People talk of production and distribution. Some of our friends and their categories talk that only there should be production. They cannot talk of distribution. That is wrong argument.

There is a real meaning of socialism. Even to the extent you have production in the country, it should be distributed equitably among all citizens. No use of talking of concentration of wealth and defending the monopolists on the one hand and talking of unemployment. So it all looks so funny. I think we are the only people who can solve this problem. Our party can alone do it and not our friends that side. Nobody will have confidence that they will be able to tackle this problem.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BAL GOVIND VERMA) : Shri Bharat Singh Chauhan is trying to bring about a change in Art. 43 of the Constitution. Under this Art. 43 of the Constitution there is a directive provided in the Constitution to the State that the State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

What is Mr. Chauhan asking us for in this amendment ? He is asking for four things One is that he is putting a ceiling for us He is fixing a date by which work should be provided to all the able-bodied persons in the country. That is, he wants that work should be provided to all the persons who can work and that too by 1976. The second thing he wants is a living wage equivalent in its purchase value to the purchase value of money prior to the independence of the country and the third in the conditions of work ensuring full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities failing which the President may thereafter form a multi-party Government based upon the talent which he may consider proper. I will be dealing with the

first three things. My colleague, the Law Minister, will deal with the fourth. As a matter of fact, he will be dealing with this matter but, as I am intervening, I will be taking up the three things.

So far as the work to be given to all able-bodied persons is concerned, nobody can differ from him. I think it will be the duty of the Government and the Government is alive to its duty The Government consider that it should and it is trying to give employment to as many persons as is possible within the limited resources. Within the existing resources the Government is trying to provide jobs.

Now, the question arises as to how many persons are there to whom job is to be provided. This is a thing to be noted down. It is very easy to say but very difficult to do. Unless the resources are there, how can you provide jobs only by bringing about legislation or only by a party "*elan*" You cannnot bring about a change. You cannot give jobs to all these persons. So, there must be development and economic development of such a level that proper resources should be created whereby it may be possible to provide iobs to all the able-bodied persons I may give you a little of the background. Here, everybody is saying, Government should provide jobs And. Government is committed to providing jobs. This is quite evident from the Manifesto of our party, issued at the time of the elections. But, the question is this. How are we know as to how many persons are there who are to be provided with jobs ? Our only sources of information are the Employment Exchanges. There are the live registers. They give the information. Even that information is not correct. Our Director General, Employment and Training conduced some survey. They wanted to know about this, because we asked them to find out many among those who registered themselves with the Employment Exchanges have been actually without work and what is being done there.

17.00 hrs.

They conducted a survey. Out of 100 persons, 50 persons were really without jobs. They wanted jobs. Out of remaining 50 persons, 43 persons were such who were employed somewhere else, but they got their names registered in the employment exchanges with the hope to get some better jobs. Then, 7% of persons were studying in schools and colleges They said they would give up study if they could get some suitable jobs ; this is the condition. Therefore, it is rather difficult to find out how many persons are without jobs.

For this purpose, we propose to ask the State Governments to conduct a special survey try to find out as to how many persons on the live register of Employment Exchanges are really without jobs. It is also proposed to conduct surveys through the N.S.S. in rural and urban areas and arrive at estimates to show how many persons are actually unemployed so that some schemes worth taking may be started. This is the position.

We share the anxiety of hon. Members. I may tell them that the Government of India are very much alive to their duties in this regard and they have this aim in view. If you look to the Fourth Five Year Plan, you will know how sincere the Government of India are on this point. The Government of India have asked various Ministers to give a fresh look with a view to provide as many job opportunities to the poor as is possible. If you glance through the Fourth Five Year Plan, you will come to know the real picture of it. You know in the Fourth Five Year Plan every effort has been made to increase the employment opportunities ; particularly the emphasis has been laid so that the poor and weaker sections of society may be provided with all sorts of assistance, so that they may be able to sustain themselves. At the same time, special attention has to be paid towards those areas which are said to be backward areas.

I suppose my hon. friend Shri Bharat Singh Chauhan himself hails from the rural area. and as he himself must be knowing, in rural areas, special emphasis has been laid on the agricultural side. Whether a person is a small farmer or a marginal farmer or a big farmer, every effort is being made to provide assistance to him in any form that he required, so that his condition of living may improve. Hon. Members know that for this purpose, Government have issued instructions to all the developmental agencies as well as the nationalised banks to extend all sorts of facilities to the farmers so that they may bring about improvement in the working of their agriculture, and this is giving employment to so

[Shri Bal Govind Verma]

many persons in the villages. Not only those who are without jobs are getting employment. about even those who are highly technically qualified are getting jobs there. Those people who were going without jobs in the rural areas are now getting jobs, because even the small farmers are trying to raise three or four crops a year and they are trying to practise intensive cultivation and wherever there is intensive cultivation, more labour is required. and, therefore, that labour which was surplus there is now finding work there, Those bigger farmers who could do their work themselves before now find it difficult to carry on their cultivation without the assistance of a technically qualified person. In this way we see that in the rural areas some sort of awakening is there. Everybody is realising that he has to go forward. This awakening is there not only among the farmers but even among the landless labour. Many people have come forward and told us that because of this rural employment crash programme which is going on, people are not coming forward to work on a wage of Rs. 100 p.m. This shows that there is awakening in them and they are also eager that their wages should increase and accordingly they go wherever they can get higher wages and thus they are going in search of places with higher and higher wages.

Similarly, so far as the trained technical personnel are concerned. they are given further vocational guidance and further training is also given to them. Other avenues of training have also been opened to those people so that specialised jobs which are awaiting outside may be available to them.

Since the time at my disposal is very short, I would briefly say that so far as all the developmental activities are concerned, whether they be in communications or in electricity or in road-building etc., everywhere, the schemes are all labour-oriented, and it is the hope of Government that most of the people will be absorbed there.

Then, a question has been raised whether the wages are equivalent to the purchase value which they had before Independence. I think the hon. Member must be aware, since he has talked about it, that it is not only not possible but it is unimaginable that the wages should be equivalent to their purchase value before Indepndence. That is the position not only in India but also elsewhere. If he looks at the countries abroad, he will find that the standard of living has increased and the cost of materials or things has also increased.

As a result, it is not possible to restore the purchase value which existed prior to independence. At the same time, the purchasing power has not gone down because through the several wage boards set up there has been a constant effort to increase the wages of workers commensurate with the rise in the cost of living index prevailing at respective times. From time to time Labour Commissions are also being apointed to take an overall view and suggest ways and means to bring about increase in wages and other amenities to be provided to labour . There is the Minimum Wages Act, 1948, which has done yeomen service to labour. Hours of work are being regulated. Managements of factories are asked to provide all possible means of enjoyment by way of social, cultural and other recreational facilities. Since the hours of work have been limited, labour can engage in these activities as well.

In the light of all this, the hon member should not feel that nothing is being done in the field. Whatever he has suggested will not remain a directive but a direction. How far the law will work will of course depend on co-operation from all sides. In view of my clarifications, I do not think it is necessary to proceed with the Bill and I hope that the Mover will withdraw it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHURY) : The objectives sought to be secured through the amending Bill can, if I may be permitted to do so, be divided into four parts : (1) to provide work to all the workers, (2) a living wage equivalent to its purchase value of money prior to independence, (3) conditions of work ensuring for each worker leisure, social and cultural opportunities, and (4) failing these, the President should form a multi-party party Government. The Mover has fixed a timelimit for achieving these, before 1976.

More employment can result only from increased economic activity and Government is doing its best to step up the pace of

such activity. State action alone cannot ensure a living wage to the workers. A joint effort has to be made by the workers, the employers and Government.

Government are seized of the problem of unemployment and are taking all possible steps to tackle it reasonably and achieve a solution as speedily as practicable. Considerable emphasis has been laid on labour-intensive schemes in rural areas such as roads, minor irrigation, soil conservation, rural electrification, village and small industries and housing. Specific programmes like the establishment of development agencies for small farmers and for the sub-marginal farmers and landless labour are *inter alia* intended for the generation of increased employment.

A scheme for rural works programme in the chronically drought-affected areas has been taken up which is designed to cover 53 districts which have already been identified.

Sir, special emphasis has also been placed on the development of small and rural industries and various measures are being taken for the development and strengthening of infra-structure facilities like industries estates and the provision of necessary inputs like cheap credit, raw meterials and technical knowhow; liberal credit facilities are being extended for the establishment of small industries. A programme to establish ancillary industries around large public sector undertakings also has been initiated.

Special schemes are also being sponsored by the financial institutions including nationalised commercial banks to enable the young technical personnel to establish small industries and other vocations for self-employment. National Small Industries Corporations are also extending hire purchase facilities for setting up small industries.

Large-scale investments envisaged in the industry and minerals, transport, communications and power are also likely to help in the growth of non-farm employment.

My colleague has already spoken about the crash programmes and so I will not say about them. A special provision has also been made for the current year to initiate a programme for tackling the problem of educated unemployed.

Thus, the Government are taking all possible steps to increase the employment opportunities and wages for all sections of the community consistent with the availability of resources for development.

Government has, through planned development, consistently aimed at raising the standard of living. Over the first three Plans, per capita income at 1948-49 prices rose by as much as 20.5 per cent. There can be no doubt that there has been substantial improvement in *per capita* income in relation to the period immediately preceding Independence.

It is the firm intention of Government to persist in the development effort, thereby increasing the total resources available to raise living standards and for further savings and investment, to promote equality of income distribution, and in particular, to ensure progressive improvement in the living standards of those enjoying relatively low levels of consumption.

The proposed article requires the State to secure a living wage equivalent in its purchase value to the purchase value of money prior to the Independence of the country. The proposed article puts a time-limit of five years within which the living wage ensuring a purchase value equivalent to the pre-Independenee purchase value of the rupee should be secured and further provides that in case the present Government fails to do so, the President should form a 'multi-party Government' based upon the talent which he may consider proper.

May I draw the attention of my hon. friend to articles 74 and 75 of our Constitution These articles require the President to act on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. Although the President has the power to appoint the Prime Minister, he has no power to appoint the Ministers except on the advice of the Prime Minister. It is not, therefore, possible for the President to form a 'multi-party Government' unless the Prime Minister wishes to form such a Government.

The proposed provision, therefore, seeks to give a power to the President which is contrary to the provisions of article 75 (1) of the Constitution.

The President is the head of the State; he is not the head of the Government, and

[Shri Nitiraj Singh Chaudhury]

he cannot take any executive action except on the advice of the Council of Ministers. The proposed provision is, therefore, not only against the express provisions contained in the Constitution but also against the entire structure of the Government based on the present Constitution.

Therefore, I oppose this Bill.

श्री भारत सिंह चौहान : सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको ट्रेजरी बेंचेज और विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एकमत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 24 सालों से देख रहे हैं।

मन्त्री महोदय ने यहां पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में गवर्नर का राज स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहां की व्यवस्था, वहां का विकास ठीक नहीं हो रहा है। जब किसी राज्य में अव्यवस्था फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जवाबदारी से लोग काम न करते हों तो वहां पर गवर्नर राज स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद है। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति सार्वभौम है और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है इमर्जेन्सी के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की तरक्की के लिए जवाबदारी अपने हाथ में न ले सकें। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जवाबदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति में जवाबदारी वेस्टेड है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि संविधान में आदिवासी, हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि दस साल में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार दस साल के लिए बढ़ाया गया और दौबारा फिर दस साल के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल फेल हुई है। पिछले समय में सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में यह जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते हमारे देश का जो नक्शा हम सोच रहे हैं समृद्धिशाली बनाने का वह केवल एक स्वप्न ही रह जायेगा। ऐसी हालत में मैं अनुभव करता हूं कि इमर्जेन्सी डिक्लेयर की जाये और इस देश के जो टैलेन्टस हैं उनको लेकर सर्वदलीय शासन स्थापित किया जाये। इमर्जेन्सी के रूप में इसको किया जा सकता है। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे इस देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है बल्कि इस सरकार की बेअक्ली से दिन प्रति दिन समस्यायें बढ़ती ही जा रही हैं। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि यह सरकार एक तरफ तो लोगों को रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ इस सरकार की अदूरदर्शिता के कारण इस देश में 80 लाख बेकार लोग और भी आ गए हैं। आखिर मंत्री महोदय इस समस्या का क्या मूल्यांकन करते हैं ? जिस चीज को वह दूर करने की बात करते हैं वही चीज और उनके सिर पर आ जाती है।

यह सरकार कहती है कि पिछले 24 सालों में हमने इस देश में लघु सिंचन, सहकारिता

और उद्योगों का जाल फैलाया है लेकिन जब व्यवहार में हम देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। हर जगह राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। सेन्टर की कोआपरेटिव कमेटी में मैं भी था। वहां पर तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स आये थे। वहां पर इस बात का डिस्कशन हुआ कि कोआपरेटिव के जरिए हम भारत की बहुत तरक्की करेंगे लेकिन उन्होंने यह अनुभव किया कि जो कुछ इस समय हमने देश में जाल फैलाया है वह असफल हुआ है। हो सकता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ सफलता मिली हो लेकिन शेष सारे भारत में कोआपरेटिव के जरिए से जो हम देहातों में रोजगार देने की बात सोच रहे थे उसमें असफलता ही हाथ लगी है। यह बात केन्द्रीय समिति की बैठक में महसूस की गई कि उसमें हम असफल हुए हैं। तो आप किस तरह से इस समस्या को हल करना चाहते हैं? एक चीज हमें दिखाई देती है कि कई राज्य हैं जहां सड़क निर्माण की योजनायें हैं लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहां पर सड़कों का बड़ा अभाव है। दर-असल में अगर सरकार का इरादा हो और एक प्रतिज्ञा के साथ इस बात की कोशिश करें कि हमें बेरोजगारी को हल करना है तो मैं इस बात में सहमत हूं कि लघु सिंचन योजनाओं के द्वारा, सहकारिता के आधार पर तथा सड़क निर्माण और छोटे छोटे उद्योगों के लिए अगर ईमानदारी से काम किया जाये तो करोड़ों लोगों को इस देश में धंधा मिल सकता है। लेकिन अनुभव बिल्कुल इसके विपरीत ही बतलाता है क्योंकि दिन प्रति दिन हम इस बात को देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग बेकार होते जा रहे हैं। यह डिफेक्टिव सिस्टम आफ एजूकेशन है जिसकी वजह से लाखों की तादाद में इंजीनियर्स बेकार हो गए हैं। इसमें परिवर्तन करने की क्यों सरकार को हिम्मत नहीं होती है? आपको यह सोचना होगा कि जब तक हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी बल्कि दिन प्रति दिन बढ़ती ही जायेगी।

जहां तक देहातों का प्रश्न है, हम देखते हैं कि करोड़ों की तादाद में भूमिहीन और खेतिहर मजदूर बेकारी के शिकार हैं। साल भर में उनको केवल दो तीन महीने का धंधा मिलता है और बाकी समय वे बेकार रहते हैं।

यहां पर बैंक राष्ट्रीयकरण का उदाहरण देकर कहा गया कि बैंक राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया है कि बेकारों को रोजी मिले लेकिन अनुभव यह बतलाता है कि बैंकों ने ऋण देना भी बन्द कर दिया है। मुझे इस बात का व्यक्तिगत अनुभव है अपने क्षेत्र का कि राज्यों में बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऋण न दिया जाये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: यह बात गलत है।

श्री भारत सिंह चौहान: यह बिल्कुल सही है ऐसे रिजिड रूल्स बनाये गये हैं जिससे भूमिहीनों को कोई लाभ नहीं मिल सकता है या जिनके पास कोई धंधा नहीं है उनको कोई लाभ नहीं मिल सकता है। इस तरह के आपके नियम बने हुए हैं आप कितना ही कहें कि बैंक राष्ट्रीयकरण से हम बेकारी दूर करेंगे लेकिन आज अनुभव की बात यह है कि बैंक राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं हुआ है। जिस तरह से बेचारे गरीब किसान एक क्लेक्टर के पास जाने से डरते हैं वही स्थिति बैंकों की भी हो गई है। आपने बिजनेस को चौपट कर दिया है। आज इन बैंकों में जो मैनेजर या एजेंट बैठे हुए हैं वे अपने को क्लेक्टर से कम नहीं समझते हैं। उनका उसी प्रकार का डर और भय बेचारे गरीब किसानों पर छाया हुआ है जैसा कि एक क्लेक्टर का होता है। इन सभी बातों को देखते हुए मैंने यहां पर यह बिल पेश किया है। या तो फिर यह सरकार इस बात का प्रण और प्रतिज्ञा करे कि हम इस अवधि के भीतर बेरोजगारी की समस्या को हल करेंगे क्योंकि जब तक इस तरह की प्रतिज्ञा नहीं की जायेगी तब तक भारत का कल्याण होने वाला नहीं

[श्री भारत सिंह चौहान]

है भले ही आप कितनी अच्छी योजन यें बनायें। अनुभव से जब हम इन योजनाओं को देखते हैं तो यह लगता है कि उनका दुरुपयोग ही किया जाता है, कोई लाभ नहीं मिलता है।

आप एक तरफ पब्लिक सेक्टर को बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को समाप्त कर रहे हैं, उनके सारे इन्सेंटिव्ज को खत्म कर रहे हैं। आज आपका जिस तरह का शासन है उसका एक आदर्श हमारे सामने मौजूद हैं कि सेंकड़ों मिलें बेकार पड़ी है और बन्द हो रही हैं। छोटे छोटे उद्योग-धंधे ठप्प हो रहे है आप की इन नीतियों के कारण। जिस तरह से आप पब्लिक सैक्टर की तरफ ध्यान देते हैं उस तरह से निजी सैक्टर की तरफ नहीं देते हैं। बल्कि उसको आप डिसकरेज करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे जो हमारे देश में लाखों और हजारों की तादाद में बढ़ने चाहियें, नहीं बढ़ रहे हैं। देश में मिलें बन्द पड़ी हैं और हजारों लाखों मजदूर बेकार हैं। इस प्रकार के अनुभव हम को रात दिन हो रहे हैं। इसलिए मैं शासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उसने समय की सीमा बांधकर हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया तो इसके जो नतीजे होंगे वे खतरनाक होंगे। इस वास्ते एक निश्चित अवधि के भीतर उसको इस समस्या को हल करने की घोषणा करनी चाहिये।

I beg to move for leave to withdraw the Constitution (Amendment) Bill.

MR. CHAIRMAN : Before taking up this motion, I have to dispose of the amendment moved by Shri Daga. I find that he is not here. I will now put his amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to withdraw the Constitution (Amendment) Bill."

The motion was adopted.

SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN : I withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

17.30 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Insertion of New Article 16A*) by Dr. Karni Singh

DR. KARNI SINGH (Bikaner) : I beg to move :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

I would like to speak in support of my Constitution (Amendment) Bill No. 13, which tries to bring about an amendment of the fundamental rights chapter by inserting a new clause 16A, which would read :

"16A. (1) All adult citizens shall have the right to work and shall be entitled to adequate means of livelihood.

(2) Failing to procure such livelihood as referred to in clause (1), every citizen shall be entitled to an unemployment allowance to be paid by the State."

A few weeks ago I had the honour once again to move a similar Bill, trying to get free compulsory primary education for the country and to get Parliament to accept old age insurance, help to the poor, to the infirm, old and so on. The Bill that I have introduced is in line with the mood of the House, which was expressed by members from practically every side of the House, when it was mentioned very clearly and in emphatical terms that unless something was done positively to eradicate poverty in this country, to find job for our teeming millions, this country would face revolutionary conditions. I say that in keeping with the very words spoken by the Prime Minister and other Ministers opposite and members of this hon. House as the Constitution 24th (Amendment) Bill yesterday, I commend this Bill to the House with a request that this may please not be taken as a Bill coming from the opposition benches but a